ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-2* Issue-11* December (Supplementary Issue)-2017
Innovation The Research Concept

छत्तीसगढ़ राज्य की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में उपलब्ध प्रशासनिक एवं वित्तीय सुविधाओं के विषय में उनके शिक्षक प्रशिक्षको का प्रत्यक्ष बोध का अध्ययन

विनीता सिंह
व्याख्याता,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
शा. उ. मा. शाला कैम्प –1,
भिलाई, छत्तीसगढ़

सारांश

शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) मे विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर इन लक्ष्यो की पूति में संसाधनों की पूति का दायित्व न्यूपा एन.सी.ई.आर.टी. नयी दिल्ली का रहा है। राज्य स्तर पर यह दायित्व SCERT निभाते है तथा जिले स्तर पर यह दायित्व एवं प्रशिक्षण का दायित्व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाईट्स) को दिया गया है।

जिनका लक्ष्य दो वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित कर प्रारम्भिक शालाओं हेतु प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करने का है। इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष राज्य की डाईट्स की समोन्नति की योजना बनाने तथा उन्हें कारगर बनाने हेतु तथ्यात्मक जानकारी प्रदान कर सकेंगे।

मुख्य शब्द : न्यूपा, एन.सी.ई.आर.टी, SCERT, डाईट्स, शिक्षक प्रशिक्षको, लोकव्यापीकरण, प्रौढ़ शिक्षा।

प्रस्तावना

भारत मे केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय साक्षरता संबंधी कार्यनीतियों को जमीनी स्तर पर अकादमिक सहयोग देने और संसाधनों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1987 से देश के प्रत्येक राज्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गयी। इस प्रकार दो दशकों से अधिक समय से संचालित इन संस्थानो के ध्येय (mission), भावी दृष्टि (vision) तथा लक्ष्य (goal) संबंधी प्रगति के आंकलन का उपयुक्त समय अब आ गया है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूपा एन.सी.ई. आर.टी. नयी दिल्ली द्वारा इस दिशा में प्रयास भी किये गए हैं।

नवोदित राज्य छत्तीसगढ़ 1 नवम्बर, 2000 को अस्तित्व में आया, देश के अन्य राज्यों की तरह यहां भी प्रत्येक जिले में एक डाईट की दर से डाईट्स स्थापना का लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया गया है, इन्हे दो वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित कर प्रारम्भिक शालाओं हेतु प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करने का दायित्व दिया गया है।

इस प्रसंग में यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं सार्थक है कि नवोदित छत्तीसगढ़ राज्य अपने यहां के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाईट्स) के गठन व संचालन में विशेष सजगता बरते और देश के अन्य राज्यों की डाईट्स की कार्यप्रणाली की सकारात्मकता एवं नकारात्मकता को जानकर यहाँ की डाईट्स को उद्देश्यपरक बनायें। इसके लिए अत्यन्त आवश्यक है कि अपनी राज्य सरकार यहाँ की डाईट्स में सुयोग्य व जागरूक शिक्षक – प्रशिक्षक नियुक्त करें जो संस्थान को अधिक उद्देश्यपरक बना सके। यह किस सीमा तक हो सका है? इसका पता लगाने, राज्य की वर्तमान डाईट्स में कार्यरत शिक्षक – प्रशिक्षकों के अपनी डाईट्स के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष बोध मापने, के उद्देश्य से यह शोधकार्य लिया गया है, जो अत्यन्त प्रासंगिक है। इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष राज्य की डाईट्स की समोन्नति की योजना बनाने तथा उन्हें कारगर बनाने हेतु तथ्यात्मक जानकारी प्रदान कर सकेंगे।

साहित्यावलोकन

ऐसे कुछ प्रमुख शोध निष्कर्षो का उल्लेख संदर्भ हेतु निम्नानुसार दिया गया है :– प्रोफेसर के.पी. पाण्डेय ने अपने लेख में उल्लेख किया है कि अध्यापक – शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर गठित डाईट एवं माध्यमिक स्तर पर गठित शिक्षक महाविद्यालय एवं उच्च अध्ययन संस्थानों के अस्तित्व में आ

जाने के बाद भी सेवापूर्व प्रशिक्षण में अपेक्षित गुणवत्ता का आयाम नहीं जुड़ सका है। यदि इनके पाठ्यक्रमों, अध्यापक शिक्षा के लिए नियुक्त शिक्षकों, प्रशिक्षकों तथा कार्यक्रम की गुणवत्ता के प्रमुख मानकों – कुशलता, प्रतिबद्धता, उपलब्धि एवं उत्कृश्टता का अनुप्रयोग कठोरतापूर्वक किया जाए तो लगभग 5 प्रतिशत संस्थायें भी खरी नहीं उतर पायेंगी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के कतिपय डाईट्स के सर्वेक्षण से दीपा कृष्ण एवं रोज आनन्द (अन्वेशिका, अंक 3–2,दिसम्बर 2006,पृष्ठ 75–80) ने ऐसा ही अध्ययन करके अभिमत दिया है कि संस्थाओं में भौतिक सुविधाओं की कमी है, पुस्तकालयों में पुस्तकों की कमी, प्रयेगशालाओं की कमी, उच्च शैक्षिक योग्यता वाले शिक्षक – प्रशिक्षकों की कमी है। इस प्रकार राज्य के डाईट्स उस लक्ष्य की पूर्ति से काफी दूर हैं जिसके लिये इनकी स्थापना की गयी थी। प्रोफेसर चन्द्रशेखर (2007) ने आन्ध्रप्रदेश के डाईट्स के व्याख्याता–प्रशिक्षकों के प्रत्यक्षीकरण का उल्लेख करते हुए लिखा है कि राज्य के डाईट्स संसाधनों से सुसज्जित नहीं हैं और उनमें संसाधनों की कमी है।

डॉ0 एस. मुखोपाध्याय, प्रेमिला मेनन तथा बी.के. पण्डा ने संस्थागत मूल्यांकन (1992) के अन्तर्गत हरियाणा की कतिपय चुनी हुई डाईट्स का मूल्यांकनात्मक अध्ययन किया और उनके निष्कर्ष निम्नानुसार रहे – अध्ययनान्तर्गत हरियाणा के डाईट्स में आधारभूत संरचना, सिविल वर्क्स, छात्रावास, आदि की सुविधा पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। डाईट्स में प्रयोगशाला बनाने का प्रयास नहीं किया गया है। कम्प्यूटर उपकरणों का उपयोग यथोचित नहीं पाया गया। हरियाणा सरकार को यह सोचना होगा कि डाईट्स से प्रशिक्षत + 2 स्तर की योग्यताधारी शिक्षक कक्षा आठवीं में पढ़ाने हेतु कहाँ तक उपयुक्त हो सकते हैं ? शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का डाईट्स के अकादमिक तथा प्रशासकीय समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित राज्य सरकारों से बातचीत करनी चाहिए। मात्र वित्तीय सहायता देने से डाईट्स को प्रभावशाली ढंग से संचालित नहीं किया जा सकता।

रंसूल, जी., कौल लोकेश, तथा के. वर्मा (1989) ने जम्मू तथा कश्मीर की डाईट्स का मूल्यांकन करते हुए सुझाव दिया है कि डाईट्स को स्वतंत्र तथा स्वशासी होना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि जिला शिक्षाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में एक परामर्शदात्री समिति बनायी जानी चाहिए जो डाईट्स के संचालन हेतु दिशा – निर्देश दे।

उत्तरप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, हरियाणा तथा जम्मू – कश्मीर में डाईट्स के उपरोक्तानुसार मूल्यांकन अध्ययन निष्कर्षो से स्पष्ट है कि इन राज्यों में डाईट्स अपेक्षानुकुल प्रभावशाली ढंग से क्रियाशील नहीं है और उनके सही संचालन हेतु राज्य हेतु सरकारों एवं केन्द्रीय सरकार को आगे आना होगा।

उपरोक्त निष्कर्षो के आधार पर छत्तीसगढ़ के डाइट की यथास्थिति का भी मूल्यांकन करना उचित प्रतीत होता है। इसी दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन की सार्थकता प्रतीत होती है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. डाईट्स की प्रशासनिक सुविधाओं का अध्ययन करना।
2. डाईट्स में आबंटित वित्तीय सुविधाओं का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना

$H0_1$

राज्य की डाईट्स की प्रशासनिक सुविघाओं के विषय में शिक्षक प्रशिक्षको का प्रत्यक्षीकरण सकारात्मक नहीं है।

H02

राज्य की डाईट्स की वित्तीय सुविधाओं के विशय में शिक्षक प्रशिक्षको का प्रत्यक्ष बोध सकारात्मक नहीं है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन एक वर्णनात्मक अध्ययन है जिसमें सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया हैं।

न्यादर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में जिला प्रशिक्षण संस्थाओं के 141 उत्तरदाता सम्मिलित हैं।

उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षक प्रशिक्षको के अभिमत को जानने हेतु NCERT, New Delhi के प्रोफेसर के चन्द्रशेखर (2007) द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष बोध मापनी का उपयोग किया गया है। मापनी के मूल निर्माता की अनुमति से इस प्रत्यक्ष बोध मापनी को हिन्दी भाषी क्षेत्रों में उपयोग हेतु हिन्दी में अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुवादित किया गया है तथा उसे नियमानुसार अनुकुलित किया गया है

निष्कर्ष

प्रशासनिक सुविधाओं पर शिक्षक प्रशिक्षकों का मत निम्नानुसार हैं –

1. छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकांश डाईट्स में नियमित एवं मानक के अनुकूल योग्य प्राचार्य नियुक्त नहीं है।
2. डाईट्स की प्रयोगशालाओं एवं कार्यालयों में टेक्नीकल स्टाफ पर्याप्त संख्या में नियुक्त नहीं है।
3. शिक्षक–प्रशिक्षक व्याख्याताओं को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाने तथा उपने प्रभावशाली निरीक्षण से व्याख्याताओं को सजग व क्रियाशील बनाने के सम्बन्ध में प्राचार्य सक्रिय रहते हैं, ऐसा उत्तरदाताओं ने माना है।
4. छात्रावासों में पर्याप्त स्टाफ नहीं हैं।
5. अधिकांश शिक्षक–प्रशिक्षकों ने माना है कि उचित अवसर आने पर अधिकांश प्राचार्य संस्थान के विकास हेतु स्थानीय लोगों की सहायता तलाशते हैं परन्तु ऐसा न मानने वाले उत्तरदाता भी पर्याप्त हैं।
6. अधिकांश शिक्षक – प्रशिक्षकों ने अपने प्राचार्य को अपना रोल मॉडल माना है जो उनका निरीक्षण करके उन्हें रचनात्मक सुझाव देते हैं। प्राचार्य छात्राध्यापकों की क्षमता में विश्वास रखते हैं। संस्था में अच्छा वातावरण बनाने के लिए कड़े प्रशासनिक नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं।

7. छात्राध्यापकों को अधिकांश प्राचार्य अकादमिक सुविधायें उपलब्ध नहीं करा पाते।
8. प्राचार्य शिक्षक–प्रशिक्षकों के अनुसार डाईट्स व्याख्यताओं की नियुक्ति नियमित रिक्रुटिंग एजेन्सी के माध्यम से होनी चाहिए।
9. संस्थान के व्याख्याताओं के सेवा नियम सुपरिभाषित हैं।
10. प्रयोगशालाओं एवं ग्रन्थालय में योग्य टेक्नीकल स्टाफ की नियुक्ति आवश्यक है। उसी प्रकार छात्रावासों में पर्याप्त कर्मचारी तथा संस्थान में व्यायाम – शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्यतः की जाए।
11. संस्थान के गार्डन के रख–रखाव के प्रति प्राचार्यो में गहरी रूचि का अभाव पाया जाता है। छात्राध्यापकों द्वारा अध्यापन में अधिक से अधिक अध्यापन शिक्षण सामग्री का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने तथा अध्यापन सम्बन्धी उनकी त्रुटियों को सुधारने के प्रति प्राचार्यो का रूझान न्यून पाया गया है।

वित्तीय सुविधायें के निष्कर्ष

वित्तीय सुविधाओं पर शिक्षक–प्रशिक्षकों का मत निम्नानुसार है–छत्तीसगढ़ राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य प्रारम्भिक शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थायें यद्यपि आर्थिक दृष्टि से सक्षम है परन्तु प्राचार्यगण आर्थिक आबंटनों का उपयोग संस्थान में अकादमिक कार्यो के विकास में करते हैं, इस पर उत्तरदाताओं का प्रत्यक्षीकरण स्पष्ट नहीं हैं।

अन्य सुविधाओं संबधित निष्कर्ष

इस शीर्षक में अन्य प्रमुख सुविधाओं विशेषकर अन्तरपारस्परिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित निष्कर्ष निकले गए हैं :–

1. जन–कल्याण से जुड़े स्थानीय लोग संस्थान के विकास में सहायता करने के प्रति कम रूचि लेते हैं।
2. छात्राध्यापकों ने स्वीकारा है कि वे संस्था परिसर के विकास करने की आदतों को प्रोत्साहित करते हैं।
3. प्राचार्य द्वारा शिक्षक–प्रशिक्षकों की आलोचनायें रचनात्मक होती हैं।
4. प्राचार्य, व्याख्याताओं द्वारा पूर्ण क्षमता से कार्य करने के प्रति आश्वस्त होते हैं।
5. ब्लॉक – टीचिंग के समय कॉलेज – यूनिफॉर्म में रहना उपयोगी है।
6. अधिकांश डाईट्स में ग्रन्थालय सलाहकार समिति भली भाँति कार्य नहीं करती।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *चन्द्रशेखर, के (2000) – एन इवैलूयेटिव स्टडी आफ प्रायमरी स्कूल एजूकेशन प्राग्राम इन आंध्रप्रदेश पी–एच.डी. थीसिस, एजूकेशन श्री वेकेटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति*
2. *चन्द्रशेखर, के (2007) "टीचर एजूकेशन पर्सेप्सन्स आफ डाईट्स फेसोलिटिज एंड दीयर व रिलेषेन्स टू सरटेन्सपर्सनल एंड डिमोग्राफिक वैरियेबल्स पर्सपेक्टिव्स इन एजूकेशन हरीनगर रेसकोर्स बड़ौदा, वाल्यूम 23 (2), अप्रैल 2007 पृश्ठः 92–104*
3. *दास, आर.सी.एण्ड जंगीरा, एन.के (2004) 'ए ट्रेण्ड रिपोर्ट, टीचर, एजूकेशन' थर्ड सवें आफ रिसर्च इन एजूकेशन नईदिल्ली एन.सी.ई.आर.टी. पृष्ठ 782–789*
4. *डेलर्स, जे.एट.आल (1996) क्वालिटी टीचर्स, लर्निंगः दी ट्रेजर विदिन रिपोर्ट टु यूनेस्को आफ दी इटंरनेशनल कमीशन आन एजूकेशन फार दी ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी पृष्ठ 146 पेरिस, यूनेस्को, कोटेड इन दी इडियंस जनर्ल फार टीचर एजूकेशन एन.सी.ई.टी. नई दिल्ली वाल्यूम 1 (1), अगस्त 1998*
5. *दीपा कृष्ण एड सरोज आनंद (2006) ''गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण–जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिका ''अन्वेशिका 3 (2) दिसम्बर 2006, पृष्ठ 75 से 80 ।*
6. *गायत्री, ए. (1996) एन इनवस्टीगेशन इन्ट परसेप्सन आफ स्टूडेन्ट टीचर्स आन देयर टीचर ट्रेनिंग, अनपब्लिस्ड एम.एड डिजस्टेशन एस. व्ही विश्वविद्यालय, तिरूपति।*
7. *सर्वशिक्षा अभियान (2008) एम.एच.आर.डी, नई दिल्ली*
8. *एस.सी.ई.आर.टी, रायपुर (2008) प्रस्तावित शालेय शिक्षा नीति।*
9. *सिंह ए.के. (2004) – मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियों बनारसीदास, नई दिल्ली*